डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 मई, 2023, डिस्पेच दिनांक 1 मई, 2023

| वर्ष 66 | अंक 23 | भोपाल | 1 मई, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

भारत को विकसित देश बनाने के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री की मंशानुरूप किसानों की आय दोगुना करने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर हुआ पूरा : मुख्यमंत्री श्री चौहान

- हमारी सरकार ने करोड़ों दीदियों को लखपति दीदी बनाया
- मध्यप्रदेश की नारी शक्ति बधाई की पात्र
- गाँव के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
- पीएम स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश में हुआ बेहतर कार्य
- समावेशी विकास के लिए हर नागरिक को जुटना होगा
- हम सब को समझना होगी "धरती की पुकार"
- डबल इंजन सरकार ने की खुशियाँ डबल
- 4 लाख 11 हजार लाभार्थियों को कराया गृह प्रवेश
- म.प्र को दी 2300 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात
- 7853 करोड़ की समूह जल प्रदाय योजनाओं का किया शिलान्यास
- ई-ग्राम स्वराज और ई-जैम एकीकृत पोर्टल का किया लोकार्पण
- प्रधानमंत्री श्री मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गाँव- गरीब का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएँ बनाई हैं, उन्हें पंचायती राज संस्थाएँ प्रभावी तरीके से जमीन पर उतार रही हैं। आज मध्यप्रदेश के विकास से जुड़ी 17 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है। यह परियोजनाएँ प्रदेशवासियों का जीवन आसान बनाने में मददगार होंगी। साथ ही रोजगार सृजन के नए अवसर भी निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में मध्यप्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कर बेहतरीन कार्य किया है। मध्यप्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाएँ स्व-सहायता समूह से जुड़ी हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्यप्रदेश की नारी शक्ति को मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस कार्यक्रम से देश के 30 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि जुड़े हैं। यह भारत के लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। हम सभी जनता के प्रतिनिधि हैं और देश तथा लोकतंत्र के लिए समर्पित हैं। "जन सेवा से राष्ट्र सेवा" ही हम सब का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देशभर की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ-साथ विशेष ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह की उपस्थिति में रीवा के विशेष सशस्त्र बल मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 लाख 11 हजार हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। साथ ही मध्यप्रदेश में जल जीवन मिशन की 7853 करोड़ रूपये की लागत की रीवा, सतना और सीधी जिलों के लिए स्वीकृत 5 बड़ी समूह जल-प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के रेल नेटवर्क के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित कर 2300 करोड़ रूपये से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास एवं शुभारंभ किया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हम विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए समर्पित भाव से निरंतर प्रयासरत हैं। विकसित भारत के लिए गाँवों की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था में सुधार और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। देश में वर्ष 2014 के पहले पंचायतों के लिए मात्र 70 हजार करोड़ रूपये का वित्त आयोग का अनुदान था, जो हमारी सरकार के दौरान 2 लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले 8 साल में 30 हजार से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया गया है। पंचायतों तक ऑप्टिकल फायबर की कनेक्टिविटी का विस्तार करते हुए 2 लाख से अधिक गाँवों में ऑप्टिकल फायबर का जाल बिछाया गया है। स्वतंत्रता के पहले से देश में व्यवस्था का आधार रही पंचायती राज संस्थाओं पर पिछली सरकारों ने भरोसा नहीं किया। पंचायतों के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया और आज परिणाम सामने हैं। पंचायतें देश के विकास की प्राण-वायु बन कर उभरी हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पंचायतों की मदद से गाँव और शहरों के बीच की खाई को कम करने की प्रयास भी निरंतर जारी है। डिजिटल माध्यम से पंचायतों को स्मार्ट बनाया जा रहा है। अमृत सरोवरों के निर्माण में ड्रोन से सर्वे कराने के साथ निर्माण प्रक्रिया में अद्यतन तकनीक का उपयोग किया गया है। आज लोकार्पित किया गया एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल पंचायतों को अधिक सशक्त और उनकी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनायेगा। आधुनिक तकनीक का लाभ प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में स्पष्टत: दिखाई दे रहा है। गाँवों के आबादी क्षेत्र के ड्रोन टेक्नोलॉजी से हुए सर्वे और मानचित्रीकरण से सम्पत्ति के संबंध में बनने वाली विवाद की स्थितियाँ निर्मूल हुई हैं। देश के 75 हजार गाँवों में इसका कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश की आधी से अधिक आबादी गाँवों में रहती है। उनकी बेहतर व्यवस्था के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 के बाद गाँवों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन और गाँवों में 3 करोड़ 75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से गाँवों के लाखों घरों में बिजली पहुँची है।

जल जीवन मिशन से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिल रहा है। इनमें से 60 लाख घर मध्यप्रदेश के हैं। पिछली सरकारों ने गाँव के लोगों का देश के बैंकों पर अधिकार ही नहीं माना। गाँव के लोगों के न बैंक में खाते थे और न ही उन्हें बैंक से कोई सुविधा मिल पाती थी। हमारी सरकार ने जन-धन योजना में 40 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक खाते खुलवाए, पोस्ट ऑफिस का उपयोग कर गाँवों तक बैंकों की पहुँच बढ़ाई और बैंक मित्र एवं बैंक सखी के माध्यम से लोगों को बैंकों से जोड़ा। इस अभियान का प्रभाव गाँवों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खेती-किसानी से लेकर व्यापार तक में ग्रामीणों को बैंकों की मदद मिल रही है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में करीब ढाई लाख करोड़ रूपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं। इस योजना से मध्यप्रदेश के लगभग 90 लाख किसानों को 18 हजार 500 करोड़ रूपए मिले हैं। रीवा के किसानों को इस निधि से लगभग 500 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं। एमएसपी बढ़ाने से गाँवों में अतिरिक्त राशि पहुँच रही है। साथ ही गाँव में रहने वाले गरीब परिवारों को कोरोना काल से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। गरीब कल्याण की इस योजना पर भी 3 लाख करोड़ रूपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। गाँवों में हो रहे इन कार्यों से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। गाँव के युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संचालित मुद्रा योजना में 24 लाख करोड़ रूपये की मदद दी गई है।

(शेष पृष्ठ 4 पर)

किसानों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले : कृषि मंत्री श्री पटेल

भोपाल : किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने किसानों को विभाग की कल्याणकारी योजनाओ का अधिकतम लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री पटेल मंत्रालय में विभागीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त और समर्थ भारत के सपने को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में पूरा करने के लिये निरंतर कार्य करना है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये हरसंभव उपाय किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल, एमडी मंडी बोर्ड श्रीमती जी.व्ही. रश्मि सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित किये गये लक्ष्यों की पूर्ति के लिये सतत् मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि उपार्जन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। किसानों को खाद के अग्रिम उठाव के लिये प्रेरित करें, जिससे कि उर्वरक भंडारण सुनिश्चित हो सके और भविष्य में किसानों को प्रत्येक परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार समय पर खाद उपलब्ध कराया जा सके।

श्री बाथम ने म.प्र. मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा भी रहे मौजूद

भोपाल : गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में श्री सीताराम बाथम ने मध्यप्रदेश मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। डॉ. मिश्रा ने श्री बाथम को नवीन जिम्मेदारी मिलने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी। राज्य शासन द्वारा श्री बाथम को राज्य केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में इंदौर विधायक श्री रमेश मेंदोला और अन्य जन-प्रतिनिधिय उपस्थित थे।

ग्रीष्मकालीन मूंग के साथ चना, मसूर, सरसों के उपार्जन की व्यवस्थाएँ दुरुस्त रहें : कृषि मंत्री श्री पटेल

ग्रीष्मकालीन मूंग समर्थन मूल्य पर 7755 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जायेगी

कृषि मंत्री ने विभागीय समीक्षा की

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर चना, मसूर, सरसों के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की उपार्जन व्यवस्थाएँ दुरुस्त रखने को कहा है। मंत्री श्री पटेल ने भोपाल में निवास कार्यालय पर विभागीय समीक्षा में यह निर्देश दिये। अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अशोक वर्णवाल, एमडी मण्डी बोर्ड श्रीमती जी.व्ही. रश्मि, विशेष सहायक श्री डी.के. शर्मा और विभागीय अपर संचालक सहित अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने आगामी खरीफ सीजन के लिये उर्वरक का अग्रिम भंडारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अग्रिम भंडारण और अग्रिम उठाव करने से किसानों को समय पर खाद मिलेगा। मंत्री श्री पटेल ने मण्डियों के आधुनिकीकरण के लिये भी आवश्यक सभी प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में आगामी समय में हरदा में मूंग महोत्सव और श्रीअन्न महोत्सव के आयोजन संबंधी चर्चा भी हुई।

बताया गया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 2 लाख 11 हजार 711 मीट्रिक टन चना, 7 हजार 374 मीट्रिक टन मसूर एवं 12 हजार 446 मीट्रिक टन सरसों खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग का 7755 रूपये, मसूर 6 हजार रूपये, सरसों 5450 एवं चना 5335 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर उपार्जन किया जा रहा है।

पीएम आवास योजना शहरी में 4616 हितग्राहियों को 46.16 करोड़ रूपये जारी

भोपाल : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 4616 हितग्राहियों को आवास बनाने के लिये 46 करोड़ 16 लाख रूपये जारी किये गये है। प्रथम किश्त के रूप में 874 हितग्राहियों को 8 करोड़ 74 लाख रूपये और द्वितीय किश्त के रूप में 3742 हितग्राहियों को 37 करोड़ 42 लाख रूपये जारी किये गये हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने निर्देशित किया है कि आवासों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

प्रदेश से 200 टन महुआ 110 रूपये प्रति किलो की दर से लंदन होगा निर्यात

भोपाल : वन विभाग के सहयोग से मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों से प्रदेश से 200 टन महुआ 110 रूपये प्रति किलो के भाव से लंदन निर्यात किए जाने का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध पिछले साल के अंत में 9वें अंतराष्ट्रीय वन मेला में लंदन की M/S O- Forest की भारतीय इकाई मधुवन्या के साथ हुआ।

राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि महुआ से पृथक से तीन गुना मुनाफा प्राप्त होगा। अनुबंधित महुआ की आपूर्ति वर्ष 2023 में की जाएगी। इसके लिए उमरिया, अलीराजपुर, नर्मदापुरम, सीहोर, सीधी और खण्डवा जिला यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन किए जा रहे है। नर्मदापुरम के सहेली वन धन विकास केन्द्र द्वारा पिछले वर्ष 18 क्विंटल खाद्य ग्रेड महुआ लंदन निर्यात किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि वनमंडल में महुआ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रूपये प्रति किलो है। लघु वनोपज की इस अद्भुत पहल से 35 रूपये प्रति किलो का महुआ 110 रूपये प्रति किलो की दर से निर्यात किया जाएगा।

खाद्य ग्रेड महुआ नेट के माध्यम से संग्रहीत

लघु वनोपज संघ द्वारा खाद्य ग्रेड महुआ को नेट के माध्यम से संग्रहीत कराया जाएगा। इसके लिए संग्राहकों को प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया है। संग्राहकों को नेट वितरण जिला यूनियन से होगा। इस विधि से संग्रहीत महुआ का फूल मिट्टी और खरवतवार रहित होते है। इससे गुणवत्ता पूर्ण महुआ संग्रहण करने से बाजार में उनकी खासी कीमत प्राप्त होती है।

जल्दी ही जावद में दो मिलेट प्रोसेसिंग इकाई लगेगी : मंत्री श्री सखलेचा

खाद्य प्र-संस्कमरण उद्योगों की स्थापना पर दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल : मिलेट मिशन के तहत दो मिलेट प्रोसेसिंग उद्योग जावद कृषि उपज मंडी परिसर में स्थापित किए जायेंगे जिससे प्रेरणा लेकर सैकड़ों किसान भी खाद्य प्र-संस्करण उद्योग लगाएं। एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने जावद में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना पर आधारित दो दिवसीय कार्यशाला एवं उन्नत कृषकों की संगोष्ठी के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही। इस मौके पर सांसद श्री सुधीर गुप्ता, सीएफटीआरआई मैसूर की संचालक डॉ. श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिह एंव वैज्ञानिकों का दल, ईएण्डवाय के प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार सांई अन्य जन-प्रतिनिधि, कृषि वैज्ञानिक एंव विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बडी संख्या में किसान उपस्थित थे।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित कर, किसान अपनी आमदनी चार गुना तक बढा सकते हैं। उन्होंने किसानों का आहवान किया कि वे कृषि वैज्ञानिकों ईएण्डवाय के प्रतिनिधियों, सीएफटीआरआई के वैज्ञानिकों से निरंतर संवाद कर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के संबंध में जानकारी हासिल करें। उन्होंने कहा कि कलस्टर में छोट-छोटे कृषि आधारित खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित कर, अपनी कृषि आय को बढ़ाएं। एमएसएमई विभाग के ईएण्डवाय प्रतिनिधि श्री सुनील कुमार सांई ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापना के लिए लगने वाली मशीनरी, आवश्यक लायसेंस, लागत, कच्चे माल की उपलब्धता, मार्केटिंग, पैकेजिंगआदि के बारे में विस्तार से बताया। उदयपुर से आये श्री प्रकाश सारस्वत ने कांट्रेक्ट फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, हर्बल आधारित उद्योग की स्थापना, मिलेट के खाद्य प्र-संस्करण उद्योग की स्थापना आदि के बारे विस्तार से बताया।

सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने कहा, कि क्षेत्र का किसान, समृद्ध, प्रगतिशील और नई तकनीक, नई खेती को अपनाने वाला किसान है। क्षेत्र के किसान कृषि में नये-नये प्रयोग करते रहते हैं। समय के साथ किसानों को खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आगे आना होगा। फूड प्रोसेसिंग कर किसान बन्धु अपने उत्पाद से अच्छा लाभ अर्जित कर सकते है। उन्होने क्षेत्र के किसानों से मिलेट के उत्पादन के लिए आगे आने का आहवान भी किया। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए सीएफटीआरआई मैसूर की संचालक डॉ. श्रीदेवी अन्नपूर्णा सिंह ने खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए तकनीकी, डेवलपमेंट, स्किल्ड डेवलपमेंट, आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता के कार्य में हर सम्भव सहयोग करने का विश्वास दिलाया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के 100 से अधिक खाद्य प्र-संस्करण, उद्योगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

देश में सर्वाधिक क्रेडिट कार्ड मध्यप्रदेश के पशुपालकों को

केसीसी धारक पशुपालकों के लिए क्रेडिट लिमिट 3 लाख, नवीन के लिए 2 लाख रूपये

भोपाल : पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि मार्च 2023 तक देश में सर्वाधिक 2 लाख 36 हजार 331 किसान क्रेडिट कार्ड मध्यप्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध करवाये गये। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से पशुपालन के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर 2 लाख रूपये तक कार्यशील पूँजी केसीसी में उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य शासन द्वारा योजना में 01 प्रतिशत सामान्य और समय पर भुगतान करने पर 04 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता दी जाती है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पशुपालन और मत्स्य व्यवसायिक किसानों की कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को पशुपालन की गतिविधियों शामिल करते हुए 3 लाख रूपये और नवीन किसान क्रेडिट धारकों को 2 लाख रूपये की क्रेडिट लिमिट दी जायेगी। केन्द्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी क्रेडिट कार्ड धारकों को 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने पर 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जायेगा।

हर आवासहीन गरीब को पट्टा देकर बनाया जायेगा भूमि मालिक : मुख्यमंत्री

सीधी जिले के गोतरा में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पत्रों का वितरण

मुख्यमंत्री ने पट्टा हितग्राहियों के साथ किया सहभोज

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर आवासहीन गरीब व्यक्ति को आवास का पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति घर बनाने के लिए जमीन के टुकडे से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अभियान चला कर हजारों एकड़ जमीन माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई है। यह मुक्त कराई गई जमीन गरीब परिवारों को आवास के लिये बाँटी जाएगी। गरीबों को गाँवों में उपलब्ध शासकीय जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो जमीन खरीद कर भी पट्टों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सीधी जिले के धौहनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोतरा में 142 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पट्टों का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मैं गरीबों का कल्याण कर जमाने को बदलने आया हूँ। हर गरीब को उसका हक मिलेगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि ऐसे भूमिहीन गरीब जिनके पास अपना घर बनाने की जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन का पट्टा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो एक छोटे से घर में संयुक्त रूप से साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार तो बड़ा होता गया लेकिन उनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है। आज का दिन गरीबों के लिए खुशी का दिन है और मैं उनकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना बहनों के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। योजना में हर पात्र बहन के खाते में प्रत्येक माह 1000 रूपये दिये जायेंगे, जिससे उन्हें अपनी और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

बहनों के हाथ का भोजन कर आत्मा प्रसन्न हो जाती है

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों के साथ बैठ कर सहभोज किया। उन्होंने परपंरागत ढंग से बने स्थानीय व्यंजनों का बड़े चाव से स्वाद लिया। बहनों के हाथों से बने स्थानीय व्यंजन कोदो और मेझरी की खीर, रिकमच की सब्जी, कटहल की सब्जी, मऊहरी पूड़ी, महुआ के लड्डू, महुआ तिली मिक्स लाटा, मूनगा के पत्ते की पूड़ी, पराठे और मक्के की रोटी का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बहनों के हाथ का भोजन कर आत्मा प्रसन्न हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि भगवान बिरसा मुंडा नगर उत्तर टोला गोतरा में 142 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पट्टा 10 मी x 6 मी साइज के चिह्नांकित कर लाटरी के माध्यम से वितरित किए गए हैं। इन प्लॉट के लिए 6 मीटर चौड़ाई की मुख्य रोड एवं 4 मीटर चौड़ाई की सहायक रोड बनायी गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा नगर में पेयजल के लिये 2 बोर और पार्क निर्मित किया गया है। साथ ही सामुदायिक भवन, आँगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, नाली, तालाब, प्राथमिक शाला इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है। आवासीय भू-अधिकार योजना में आवास पट्टा वितरण कर बस्ती को कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया है, जो सीधी जिले का नवाचार है।

जनजातीय कार्य एवं जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद श्रीमती रीती पाठक, विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह, सरपंच गोतरा श्रीमती फूलबाई पनिका सहित जन-प्रतिनिधि, हितग्राही और नागरिक उपस्थित थे।

नेशनल लोक अदालत 13 मई को

भोपाल : नेशनल लोक अदालत का 13 मई को आयोजन होगा। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री-लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जायेगा। प्री लिटिगेशन के अंतर्गत एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, लेबर एंड एंप्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर बिल एंड अदर बिल पेमेंट (एक्सक्लूजिंग नॉन कंपाउंडेबल), मेंटेनेंस केसेस, अदर क्रिमिनल कंपाउंडेबल एंड अदर सिविल डिस्प्यूट, प्लेस स्पेसिफाइ लिस्टेड केस रहेंगे। इसी तरह न्यायालय में लंबित प्रकरणों में क्रिमिनल कंपाउंडेबल अफेन्स, एनआई एक्ट केसेस अंडर सेक्शन 138, मनी रिकवरी केसेस, एमएसीटी केसेस, लेबर डिस्प्यूट केसेस, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पब्लिक यूटीलिटी सर्विस सच एस इलेक्ट्रिसिटी एंड वॉटर बिल एक्सक्लूजिंग नॉन कंपाउंडेबल मैट्रोमोनियल डिस्प्यूट एक्सेप्ट डिवोर्स, लैंड एक्विजिशन केसेस, पेंडिंग बिफोर सिविल कोर्ट/ ट्रिब्यूनल सर्विस मैटर्स इंक्लूडिंग पेंशंस केसेस, रिन्यूअल केसेस, पेंडिंग एंड डिस्ट्रिक कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, अदर सिविल केसेस में रेंट, ईजीमेंटरी राइट्स इंजंक्शन सूट्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट्स आदि से संबंधित प्रकरण रखे जायेंगे।

खाद्य लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है

सीहोर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य कारोबारकर्ता किराना , होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, एजेन्सी, फल-सब्जी विक्रेता, पानी पुरी, चाट, पोहा, समोसा ठेला वाले, पान, गुमटी, पान मसाला विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, जूस सेन्टर, आइस्क्रीम, नमकीन, कन्फेक्शनरी एवं बेकरी, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले समूह, शासकीय राशन दुकानें, शादी पार्टी में भोजन बनाने वाले केटर्स एवं हलवाई, टिफिन सेन्टर, अंडा, मटन, वेयर हाऊस, स्लॉटर हाऊस (पशु वध शाला), अनाज का व्यापार करने वाले, आटा मसाला चक्की, गुड़ विक्रेता, मेडिकल, जनरल स्टोर्स (चाकलेट टॉफी विक्रेता), एल्कोहल शराब विक्रेता, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, निर्माता एवं विक्रेता, मावा, पनीर विक्रेता, मिठाई निर्माता एवं विक्रेता, मेला हाट बाजार में दुकान लगाने वाले, मैरिज गार्डन/केटरिंग, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ परिवहन करने वाले, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल व अन्य शासकीय एवं निजी संस्थाओं में संचालित केन्टीन, प्रसाद निर्माण व विक्रय आदि एवं सभी खाद्य कारोबारकर्ता व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का उत्पादन एवं विक्रय करते हैं, सभी को लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा (केवल निर्माता/रिपैकर्स) आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

कृषि उपज मंडियों की कार्य-प्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार के लिये समिति गठित

भोपाल :राज्य शासन ने प्रदेश की कृषि उपज मंडियों की कार्यप्रणाली में प्रक्रियात्मक सुधार के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनिम, 1972 में संशोधन के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिये समिति गठित की है। कृषि उपज विपणन के वर्तमान परिदृश्य और डिजिटलाइजेशन के कारण में सुधार आवश्यक हैं।

समिति में अवर सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास श्री आर.के. गणेशे, संयुक्त संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री आर.पी. चक्रवर्ती, सहायक संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री पीयूष शर्मा, संयुक्त संचालक राज्य कृषि विपणन बोर्ड श्री अविनाश पाठे, सहायक संचालक/सचिव कृषि उपज मंडी श्री करूणेश तिवारी और कृषक प्रतिनिधि श्री कैलाश सिंह ठाकुर एवं श्री अरूण कुमार सोनी को रखा गया है।

समिति द्वारा विषयवस्तु पर विचार कर 6 माह की अवधि में सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही कार्यवाही के दौरान विभिन्न प्रभावित पक्षों-मंडी अधिकारी/कर्मचारी, कृषक, व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, हम्माल-तुलावटी से सुझाव भी प्राप्त किए जा सकेंगे।

वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार मंडी अधिनियम में संशोधन, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार तथा मंडी अधिनियम में आवश्यक संशोधन अनुरूप मंडी उप विधि में संशोधन, मंडी अधिनियम/मंडी उपविधि के दांडिक प्रावधानों के युक्तियुक्तकरण, वर्तमान में विकसित ऑनलाइन प्रणाली को ध्यान में रखकर मंडी अधिनियम/मंडी उपविधि में सुसंगत संशोधन, अनुज्ञप्ति प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन और विभिन्न कृषक, व्यापारी, हम्माल-तुलावटी संगठन से प्राप्त ज्ञापनों में प्रस्तावित कार्यवाही एवं सुधार के संबंध में समिति परीक्षण करेगी।

(पृष्ठ 1 का शेष)

भारत को विकसित देश बनाने के लिए गाँवों की....

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि धरती हमारी माँ है और माँ को मारने का हक किसी को नहीं है। खेती में बढ़ते रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग ने धरती के लिए संकटपूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों को धरती की सेहत सुधारने के लिए कृत-संकल्पित होना होगा। हम प्राकृतिक खेती अपना कर और लोगों को यह पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर अपना योगदान दे सकते हैं। पंचायतें प्राकृतिक खेती पर केन्द्रित जन-जागरण अभियान चलाएँ।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से प्रदेशवासियों को हुए लाभ, पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं और रोजगार के नए अवसरों तथा किसानों, विद्यार्थियों, कारोबारियों को होने वाली सुविधा पर भी विस्तार से प्रकाश डाला।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का रीवा में सुपारी से बनने वाले खिलौना भेंट कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश बदल रहा है। विंध्य क्षेत्र में भी रोड कनेक्टिविटी और सिंचाई क्षेत्र के साथ ही सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वचन दिया था। प्रदेश में गेहूँ, धान और सरसों का उपार्जन बढ़ा है। प्रधानमंत्री की मंशानुरूप किसानों की आय दोगुना करने का काम मध्यप्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। जल जीवन मिशन में ग्रामवासियों को घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में व्यापक स्तर पर गतिविधियाँ जारी हैं। विंध्य क्षेत्र को रेल कनेक्टिविटी के साथ नये एयरपोर्ट की सौगात भी मिल रही है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती को बचाने और पर्यावरण-संरक्षण के लिए अपनी भावनाएँ व्यक्त की हैं। प्रदेशवासी पर्यावरण-संरक्षण और धरती की सेहत में सुधार के लिए संकल्पित हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को बिजली बचाने, पानी बचाने, पेड़ लगाने, प्राकृतिक खेती को अपनाने और स्वच्छता में योगदान देने का संकल्प दिलाया।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में पधार कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ग्रामवासियों का उत्साह बढ़ाया है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी गाँव, गरीब और किसान से निकट से जुड़े हैं। उन्होंने पंचायती राज और ग्रामीण विकास की बेहतरी के लिए निरंतर प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कार्बन न्यूट्रल पंचायत, पानीयुक्त गाँव, ग्रीन पंचायत के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने मध्यप्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना और महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों की सराहना की।

एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश भर की पंचायतों के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और जीईएम पोर्टल का लघु फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय शुभारंभ किया। इस एकीकृत पोर्टल से पंचायतें सामान और सेवाओं की खरीद और उनका भुगतान डिजिटल तरीके से कर सकेंगी।

"एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल ऐप लांच

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के लिए समावेशी विकास थीम का भी शुभारंभ किया। लघु फिल्म से "एकम समावेशी विकास" वेबसाइट और मोबाइल एप को राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया गया। सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने "विकास की ओर साझे क़दम" अभियान का भी शुभारंभ किया। समावेशी विकास पर केन्द्रित इस अभियान में अंतिम छोर तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश का 1 करोड़ 25 लाखवां स्वामित्व संपत्ति कार्ड सिंगरौली जिले के ग्राम गड़हरा की श्रीमती सीता साकेत तथा श्री सूरजलाल साकेत को प्रदान किया। इसमें गाँव की आबादी भूमि और घरों के सर्वे तथा मानचित्रण के बाद भूमि स्वामियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक और अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश, देश में प्रारंभ से ही अग्रणी है। "स्वामित्व-मेरी संपत्ति मेरा हक" पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ।

2300 करोड़ रूपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगभग 2300 करोड़ रूपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। इनमें रीवा से इतवारी (नागपुर) व्हाया छिन्दवाड़ा, छिन्दवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिन्दवाड़ा चलने वाली ट्रेन का हरी झण्डी दिखाकर शुभारंभ किया। साथ ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन के 535 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास किया।

जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपये की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें रीवा जिले की 2319 करोड़ 45 लाख रूपये लागत की 1411 गाँव में पानी पहुँचाने वाली रीवा बाणसागर परियोजना, रुपये 2153 करोड़ 12 लाख लागत की रीवा और सतना जिले के 295 गाँव को लाभान्वित करने वाली सतना बाणसागर-2 परियोजना जल-प्रदाय योजना, रूपये 1641 करोड़ 52 लाख रूपये लागत की 677 गाँव में पीने का पानी पहुँचाने वाली सीधी बाणसागर समूह नल-जल योजना, रूपये 951 करोड़ 18 लाख रूपये लागत की रीवा जिले के 630 गाँव को लाभान्वित करने वाली टमस समूह नल-जल योजना और रूपये 788 करोड़ 63 लाख रूपये लागत की 323 गाँव को लाभान्वित करने वाली गुलाब सागर समूह जल-प्रदाय योजना शामिल है। इन योजनाओं से 4 हजार 36 गाँव के लगभग 9 लाख 48 हजार परिवार लाभान्वित होंगे।

"धरती कहे पुकार के" शीर्षक की सांस्कृतिक प्रस्तुति

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नवाचारों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, आजीविका मिशन, अमृत सरोवर, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए होमस्टे, हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, रीवा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजना, बाणसागर परियोजना, व्हाइट टाइगर प्रोजेक्ट और कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर केंद्रित स्टाल थे। कार्यक्रम के आरंभ में "धरती कहे पुकार के" शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति भी हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का साक्षी बनने के लिए देश की सभी ग्राम सभाएँ कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ी।

केन्द्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, केन्द्रीय जल-शक्ति एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, सांसद श्री वी.डी. शर्मा, श्री जनार्दन मिश्र, श्री गणेश सिंह, श्रीमती रीति पाठक, पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, विधायक, जन-प्रतिनिधि, केन्द्र, मध्यप्रदेश शासन और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभिन्न योजनाओं के हितग्राही और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए।

लाड़ली बहना योजना से प्रदेश में हो रही है सामाजिक क्रांति : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने मड़वास को तहसील और कॉलेज की दी सौगात

निवास को उप तहसील बनाने की घोषणा

मड़वास चौकी बनेगी थाना, मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा 50 बिस्तरीय

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पानी की कुप्पी, छाते एवं अन्य सामग्री दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने जन-सेवा मित्र तथा युवाओं से किया संवाद

मुख्यमंत्री, सीधी जिले के ग्राम महखोर में लाड़ली बहना महासम्मेलन में हुए शामिल

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के सशक्तीकरण को नया आयाम दिया है। अब लाड़ली बहना योजना प्रदेश में सामाजिक क्रांति कर रही है। यह योजना महिलाओं का जीवन बदलने का अभियान है। योजना से महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता मिलने के साथ परिवार में सम्मान और प्यार मिलेगा। एक समय था जब बेटा और बेटी में भेदभाव किया जाता था, माँ की कोख को कत्लगाह बना दिया गया था। सामाजिक जागरूकता और लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से सामाजिक परिवर्तन आया है। अब बेटियाँ वरदान बन गई हैं और उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिये जा रहे हैं। बेटियाँ, बेटों से अधिक परिवार की सेवा कर रही हैं। सरकार ने बेटियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएँ लागू की हैं। गरीब माँ-बाप बेटी को बोझ न समझे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना में बेटियों के विवाह कराये जा रहे हैं। मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जा रही है। हायर सेकेंड्री परीक्षा में गाँव में टाप करने वाली बेटी को ई-स्कूटी दी जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान सीधी जिले के मझौली विकासखण्ड के ग्राम महखोर-हिनौता में लाड़ली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने लाड़ली लक्ष्मी, आयुष्मान, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना और महिला स्व-सहायता समूहों को हितलाभ वितरण किये। मुख्यमंत्री ने मड़वास को तहसील बनाने और कॉलेज खोलने, निवास को उप तहसील बनाने, मड़वास चौकी को थाना बनाने तथा मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बिस्तरीय में उन्नयन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने 445 करोड़ 42 लाख रूपये लागत के 79 निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन और 24 करोड़ 39 लाख रूपये लागत के 39 कार्यों का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अब जमाना बदल गया है। महिलाएँ और बेटियाँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। मैं किसी भी हालत में बहनों का अपमान नहीं होने दूँगा। बहन-बेटियों की ओर आँख उठाने वालों को जेल भेजा जायेगा। लाड़ली बहना योजना के आवेदन-पत्र भरे जा रहे हैं। सीधी जिले में 1 लाख 58 हजार से अधिक आवेदन भरे गये हैं। कलेक्टर हर पात्र बहन का आवेदन-पत्र भरवायें। इस योजना के आवेदन-पत्रों का मई माह में परीक्षण कर 10 जून को बहनों के खाते में 1000 रूपये की राशि जारी की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पानी की कुप्पी, जूते-चप्पल और छाते प्रदान किये जायेंगे। संग्राहक बहनों को साड़ी भी प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई के विकास के लिए आज गोपद नदी में बाँध निर्माण का शिलान्यास हुआ है। जल जीवन मिशन से अब हर घर में नल से स्वच्छ पानी आयेगा।

सांसद सीधी श्रीमती रीती पाठक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा लाड़ली बहना योजना के लिए क्षेत्र की सभी बहनों की ओर से आभार व्यक्त किया। योजना से लाभान्वित होने वाली बहनों ने विशाल राखी भेंट कर मुख्यमंत्री का आभार माना। विधायक धौहनी श्री कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने क्षेत्र के विकास के लिए कई सौगातें दी हैं। धौहनी का पिछड़ा क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। गोंड सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण से क्षेत्र के 75 गाँवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जनजातीय कल्याण एवं जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह, विधायक सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, शरदेन्दु तिवारी, सुभाष वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह सहित जन-प्रतिनिधि, बड़ी संख्या में बहनें एवं नागरिक उपस्थित थे।

नरवाई जलाना पर्यावरण के लिए खतरनाक है - किसान भाई इससे भूसा और खाद बनाएं

भोपाल : यह देखा गया है कि किसान फसल काटने के पश्चात तने के अवशेष बचे रहेते है। इसे नरवाई कहते है। किसान नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते है। किसान नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते है।जिससे भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है तथा अग्नि दुर्धटना की सम्भावना भी बनी रहती है। कृषि विभाग ने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करने दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है। कृषक उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने की बजाए उनको वापस भूमि में मिला देते है तो निम्न लाभ प्राप्त होते है। जैसे कि कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता में वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, मृदा भौतिक गुणों के सुधार होते है, फसल उत्पादकता में वृद्धि अतः किसानों से अपील है कि खेतो में नरवाई बिल्कुल न जलाएं नरवाई का उपयोग खाद एवं भूसा बनाने में करें।

कृषि विभाग ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य पर्यावरण एवं फसल उत्पादकता को दृष्टिगत रखते हुए फसल अवशेषें को जलाने के बजाए भूमि में मिला देने से काफी लाभ होता है। फसल अवशेंषो से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ भूमि में जाकर मृदा पर्यावरण में सुधार कर सूक्ष्मजीवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। जिससे कृषि टिकाऊ रहने के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर प्रयोग अनिवार्य रूप से करे स्ट्रा रीपर यंत्र डंठलों को काटकर भूसे में बदले देता है। भूसे का उपयोग कृषक स्वयं के पशुओं को खिलाने के लिए तथा अतिरिक्त आय के साधन के रूप में भी कर सकता है।

जिले में घर - घर लाड़ली बहना के लिए स्व-सहायता समूह भी सक्रिय

भोपाल : जिले में लाड़ली बहना योजना के लिए स्व-सहायता समूह की महिलायें और मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र लगातार लोगों को जागरूक कर रहे है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए जिले में बहनों और परिवारों को जागरूक करने के लिए अनेक स्तर पर गतिविधियां संचालित हो रही है। महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं गांव-गांव में जाकर व्यापक रूप से लाड़ली बहना योजना के बारे में जानकारी दे रही और फार्म जमा करने क लिए क्या-क्या कागज की जरूरत है इस संबंध में भी सूचना उपलब्ध करा रही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ऋतुराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र महिलाएं और परिवारों की इस योजना की जानकारी दी जा रही है। घर-घर जाकर जनसेवा मित्र आधार और समग्र आईडी की अपडेशन के संबंध में बता रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन के द्वारा भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना की जानकारी भी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में 222 ग्राम पंचायतों में ई-केवाइसी अपडेशन का कार्य किया जा रहा है और आनलाइन फार्म भी जमा हो रहे है।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 23 से 60 वर्ष तक की विवाहित महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा, कागजो के सत्यापन होने के बाद पात्र हितग्राही महिला को एक हजार रूपए की राशि प्रतिमाह उनके खाते में जमा होगी।

मत्स्य सहकारी समितियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल। सहकारिता को मजबूती प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल द्वारा मत्स्य सहकारी समितियों हेतु निरंतर प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के मार्गदर्शन में प्रदेश के ग्रामीण एवं दूरदराज क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्य सफलतापूर्वक आयोजित किये जा रहे है, इसी चरण में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव (छतरपुर) एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर में दिनांक 19.04.2023, 18.04.2023, 17.04.2023, 20.04..2023, 21.04.2023, 24.04.2023 एवं 25.04.2023 को प्राथमिक कीरत सागर मत्स्योद्योग ग्राम ऊजरा (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित कसार (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित आलीपुरा (छतरपुर) मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित सटई (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, बृजपुरा जिला (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, मातगवां (छतरपुर), मछुआ सहकारी समिति मर्यादित धुडहरी (कटनी), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित सरानी (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित ईशानगर (छतरपुर), मछुआ सहकारी समिति मर्यादित चंद्रौल (कटनी), प्राथमिक मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित जटाशंकर (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित दौरिया (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित गढ़ी मरहरा (छतरपुर), मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित कैंडी/भगवंतपुरा (छतरपुर), मछुआ सहकारी समिति मर्यादित उमरियापान (कटनी) में सहकारी प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा एवं श्री हृदेश कुमार राय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव, श्री पीयूष राय सहकारी प्रशिक्षक, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को सहकारी समितियों के पदाधिकारी/प्रबंधकों अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखाकंन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराऐं, नेतृत्व विकास, मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई जाने वाली मत्स्यपालन पर योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मत्स्योद्योग कीरत सागर के अध्यक्ष श्री राजाराम रैकवार उपाध्यक्ष श्री नत्थू रैकवार सचिव श्री रामगोपाल रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति कसार के अध्यक्ष गोरेलाल रैकवार, सरपंच श्री चतुर्भुज अहिरवार संचालक श्री दरबारी लाल रैकवार सदस्य बाबू, मुन्ना, कल्लू संतोष साहू श्री चंद्र प्रकाश, श्रीमति रानी एवं चिंकू, मत्स्योद्योग समिति ईशानगर के अध्यक्ष श्री हजारी लाल रैकवार, संचालक श्री मुन्ना रैकवार, श्री चत्तू रैकवार, श्री हीरालाल रैकवार, श्री किशोरी रैकवार एवं मनमोहन रैकवार, मत्स्योद्योग समिति दौरिया अध्यक्ष श्रीमति बेटीबाई, उपाध्यक्ष श्रीमति माया राय, मत्स्य सहकारी समिति गढी मरहरा के उपाध्यक्ष श्री मूलचंद रैकवार, श्री लाल चन्द्र रैकवार संचालक एवं श्री राजकुमार रैकवार जुम्मन रैकवार, मत्स्य समिति सरानी के अध्यक्ष श्री दशरथ रैकवार, उपाध्यक्ष श्रीमति प्रेम रैकवार उपाध्यक्ष श्री पप्पू रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति कैंडी/भगवंतपुरा के अध्यक्ष श्री लखनलाल रैकवार, उपाध्यक्ष श्री गजाधर रैकवार सचिव श्री शंकर रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति मर्या बृजपुरा की अध्यक्ष श्रीमति ममता रैकवार, उपाध्यक्ष श्री करन रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति मर्या मातगवां अध्यक्ष श्री मोतीलाल रैकवार श्री जीतेन्द्र, श्री दीपक, श्री मोहनलाल, श्री धनीराम, श्री कालीचरण, श्रीमति लक्ष्मी रैकवार, मत्स्य सहकारी समिति नाथपुर छतरपुर के अध्यक्ष श्री ठाकुरदास उपाध्यक्ष श्री भगवानदास सचिव श्री शंकर प्रसाद, मत्स्य सहकारी समिति सटई के अध्यक्ष श्री खड़ी रैकवार, पूर्व अध्यक्ष बिहारी रैकवार, संचालक श्री सोनू रैकवार, श्री जीवन रैकवार, श्री हीरा रैकवार, श्री बिनोद रैकवार, श्री हरीराम रैकवार श्री भुवानी रैकवार श्रीमति नौनी रैकवार मत्स्य समिति आलीपुरा अध्यक्ष चुनुआ अहिरवार, रामस्वरूप अहिरवार इत्यादि मत्स्य समिति के सदस्य उपस्थित रहें।

वनो की सुरक्षा एवं विनाश विहीन विदोहन पर सहकारी प्रशिक्षण

भोपाल। प्रदेश की लघु वनोपज सहकारी समितियों हेतु राज्य सहकारी संघ द्वारा समाज में जागरूकता हेतु एक–एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किये जा रहे है। प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के निर्देशों के परिपालन में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के सहकारी प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे एवं श्री पीयूष राय द्वारा दिनांक 10.04.2023, 11.04.2023, 12.04.2023 एवं 13.01.2023 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित बाकल (कटनी), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित पाली (कटनी), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित खंडई (नरसिंहपुर), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित खडरा (कटनी), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित खुलरी (नरसिंहपुर), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित पानारी (नरसिंहपुर), प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित धनगवां (नरसिंहपुर), में प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिभागियों को सहकारी समितियों के पदाधिकारी/प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखाकंन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराऐं, उद्यमिता विकास से लाभ, औषधीय प्रसंस्करण, मार्केटिंग एवं वेल्यू एडीशन, औषधीयों का विनाश विहिन विदोहन, औषधीयों मार्केटिंग, उचित मूल्य कैसे प्राप्त हो एवं औषधीयों व वनो की सुरक्षा पर जानकारी प्रदाय कर समितियों के सदस्यों को लाभांवित किया गया।

प्राकृतिक खेती के लिए जनता में पहुँचे संदेश : मुख्यमंत्री श्री चौहान

प्रधानमंत्री श्री मोदी के कार्यक्रम में धरती कहे पुकार की नाट्य का मंचन होगा, मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष हुई ब्रीफिंग

भोपाल : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा आएंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होंगी, जिसमें 'धरती कहे पुकार की' नाट्य का मंचन भी होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष मंत्रालय में नाट्य की ब्रीफिंग हुई। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि नाट्य के माध्यम से लोगों में प्राकृतिक खेती का बेहतर ढंग से संदेश पहुँचे। नाट्य की प्रस्तुति प्रभावी हो, जिससे लोग प्राकृतिक खेती के लिए द्रवित हो जायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर है। पूरी क्षमता से नाट्य मंचन की तैयारी हो।

सहकारिता को मजबूती प्रदान करने हेतु-पैक्स प्रशिक्षणों का आयोजन

सास बहू (नरसिंहपुर)

गोरखपुर (डिण्डौरी)

बहरी (कंटगी)

रांकई (नरसिंहपुर)

पिपरिया (डिंडोरी)

सिल्हेटी (नरसिंहपुर)

कोकोमटा (डिंडोरी)

धनवासी (डिंडोरी)

करेली (नरसिंहपुर)

चांदपुर (डिंडोरी)

भानपुर (डिंडोरी)

बाकल (कटनी)

कंरजिया (जबलपुर)

भोपाल। प्रदेश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल द्वारा प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों हेतु एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के सहकारी प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे, श्री अखलेश द्वारा सहकारी समितियों के पदाधिकारी/ प्रबंधकों के अधिकार, कर्तव्य एवं समिति का प्रबंधन, सहकारी अधिनियम के मुख्य प्रावधान, सहकारी संस्थाओं में बैठकों का आयोजन, संचालन, वित्तीय लेखाकंन एवं अंकेक्षण, सहकारी अधिनियम की प्रमुख धाराऐं इत्यादि विषयों पर दिनांक 11.04.2023, 12.04.2023, 13.04. 2023, 17.04.2023, 18.04.2023, 19.04.2023, 20.04.2023, 21.04. 2023, 24.04.2023 एवं 25.04. 2023 को सेवा सहकारी समिति मर्यादित लिंगा (नरसिंहपुर), सेवा सहकारी समिति मर्यादित कारप गांव (नरसिंहपुर), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सिंहुडी (कटनी), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहतरा (डिडौरी), आदिम जाति बरही (कटनी), आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित गोरखपुर (डिण्डौरी), सेवा सहकारी समिति मर्यादित सास बहू (नरसिंहपुर), आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कंरजिया, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित रांकई (नरसिंहपुर), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बाकल (कटनी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित पिपरिया (डिंडोरी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सिल्हेटी (नरसिंहपुर), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित कोकोमटा (डिंडोरी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित धनवासी (डिंडोरी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित करेली (नरसिंहपुर), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित चांदपुर (डिंडोरी), प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित भानपुर (डिंडोरी) एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित बम्हनी (डिंडोरी) में पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने की प्रक्रिया एवं नवीन समिति के गठन पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

केन्द्र प्रायोजित परियोजना पैक्स कम्प्यूटरीकरण के तहत मास्टर ट्रेनर्स बेसिक ऑरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल. पैक्स कम्प्यूटराइजेशन पर राज्य सहकारी संघ में दिनांक 24.04.2023 से 26.04.2023 तक तीन सत्रों में कुल 101 मास्टर ट्रेनर्स (सहकारी बैंको के अधिकरियों/कर्मचारियों) हेतु श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिसमें जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से चिन्हित प्रत्येक 02 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। म.प्र. राज्य सहकारी संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए केन्द्र प्रायोजित परियोजना तैयार की गई हैं। परियोजना में पैक्स को भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाने में भारत में कार्यरत 95995 पैक्स 644089 गॉव और 90.8 प्रतिशत ग्रामीण नेटवर्क शामिल हैं। जमीनी स्तर पर पैक्स न केवल किसानों को ऋण प्रदान करता है बल्कि उर्वरक, इनपुट और पैदावार के विपणन जैसी अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में पैक्स के महत्व को प्रधान मंत्री के हाल के बयान से समझा जा सकता है कि, "कोई भी वाणिज्यिक बैंक शाखा कभी भी प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पैक्स) जैसी सेवाएं प्रदान करने के करीब नहीं आ सकती है।"

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाबार्ड से सौदामिनी माईणकर सहायक महाप्रबंधक, भावना यादव प्रबंधक, स्वपनिल कुमार कन्सल्टेन्ट पी.डब्लू.सी. एवं विषय-विशेषज्ञों के रूप में बैंकर्स ग्रामीण संस्थान लखनऊ (बर्ड) के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विषय-विशेषज्ञों श्रीमति स्मृति भगत (डी.जी.एम./एफ.एम) कार्यक्रम निदेशक द्वारा पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना, परिवर्तन प्रबंधन के मूल तत्व जैसे-परिवर्तन प्रबंधन क्या, क्यूं तथा सफल क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार कारक, पैक्स कम्प्यूटरीकरण के संबंध में परिवर्तन प्रबंधन, पैक्स कम्प्यूटरीकरण के पहले और

बाद का तुलनात्मक व्यवसाय विश्लेषण, हितधारकों के लिए कम्प्यूटरीकरण के लाभ, क्रियान्वयन चुनौतियां और शमन रणनीतियां, ऑडियो-विजुअल के माध्यम से पैक्स कम्प्यूटरीकरण सफलता की कहानी - उत्तराखंड का प्रस्तुति की गई । श्री निखिल कुमार (डी.जी.एम./एफ.एम) के द्वारा पैक्स कम्प्यूटराइजेशन परियोजना की आवश्यकता, परियोजना के लक्ष्य और उदेद्श्य, परियोजना क्रियान्वयन, परियोजना लागत, फण्ड का स्त्रोत और घटकवार व्यय का ब्रेकअप, पैक्स हेतु चयन के मापदण्ड, परियोजना निगरानी ईकाईयों की संरचना, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियां, बनाई गई सम्पतियों रख-रखाव और देखभाल इत्यादि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। श्री करूनेन्द्र वर्मा (एस.एम.एस.) के द्वारा कम्प्यूटर आधारभूत परिचय एवं प्रचलित कम्प्यूटर संबंधित सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एवं स्केनर, बायोमेट्रीक, पीओएस, थर्मल प्रिंटर आदि यंत्रों, कोप्सइंडिया पोर्टल और एफएचआर और एफवीआर का परिचय एवं उनके उपयोग पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण समापन अवसर पर प्रतिभागियों से परियोजना पर प्रश्नोंत्तर एवं प्रतिक्रिया सत्र के साथ कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम के सत्र समन्वयक श्रीमति मीनाक्षी बान कम्प्यूटर व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षक श्री विनोद कुशवाहा सत्र सहायक एवं प्राचार्य श्री जी.पी. मॉझी, श्री विक्रम मूजूमदार, श्री शाहिद खांन का विशेष सहयोग रहा।

कृषि साख समितियों को थोक पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने की इजाजत देगी सरकार

नई दिल्ली। देश में सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को अपने थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का विकल्प दिया जाएगा।

सरकार ने कहा कि थोक पेट्रोल और डीजल डीलरशिप लाइसेंस वाली पैक्स को यह विकल्प एक बार ही दिया जाएगा।

सरकार ने आगे कहा कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए पैक्स को नये पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इन समितियों को एलपीजी डीलरशिप भी मिल सकेगी।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ये फैसला सहकारिता मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई एक बैठक में लिया गया।

इसके अलावा बैठक में फैसला किया गया कि चीनी सहकारी मिलों को एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत एथनॉल बेचने को प्राथमिकता दी जाएगी।

बयान में कहा गया, "पेट्रोलियम मंत्रालय एलपीजी वितरण के लिए पैक्स को योग्य बनाने के लिए नियमों में भी बदलाव करेगा। पैक्स को नए पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के आवंटन के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और खेल कोटा के साथ संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी 2) के तहत रखा जाएगा।

जल जीवन मिशन में देश का माडल जिला बना बुरहानपुर

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

बुरहानपुर की महिलाओं ने जताया आभार

भोपाल : मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिलने की सबसे ज्यादा खुशी बुरहानपुर की महिलाओं को हुई है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस पर गरिमापूर्ण समारोह में बुरहानपुर कलेक्टर सुश्री भाव्या मित्तल को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सरकार और नागरिकों के परस्पर सहयोग और समन्वय का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया है।

प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार बुरहानपुर की महिलाओं के लिये अनूठे उपहार से कम नहीं है। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बहादरपुर गाँव की रेखा सुरेश सोनी अपने कठिन समय को याद करते हुए बताती हैं कि वे वर्ष 2000 में इस गाँव में बहू बन कर आई थी। पानी की परेशानी के कारण इस गाँव में कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं होता था। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। अभी शिवराज जी और मोदी जी के प्रयासों से हमारे गाँव में भरपूर पानी आने लगा है। पूरा गाँव भी हरा-भरा हो गया है। सबको साफ पानी मिल रहा है। स्वास्थ्य की समस्याएँ भी कम हो रही हैं। पहले पानी लाने में जो समय जाता था अब हम अपने दूसरे कामों में लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे लिये बहुत अच्छा काम किया है।

इसी गाँव की दीपिका श्याम सोनी बताती हैं कि गाँव में पानी से संबंधित बहुत सारी परेशानियाँ थी। नई बहुओं को भी दूर कुओं से पानी लाना पड़ता था। अब पानी मिलने से हमारी बडी समस्या खत्म हो गई है।

जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर बम्भाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच सविता प्रमोद सागर ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बताया कि हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या थी। अब हमें भरपूर पानी मिल रहा है। हर घर में पानी पहुँच गया है। सरकार ने पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे गाँव में की है। हम सब गाँव वालों और ग्राम पंचायत के तरफ से मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार मानते हैं। इसी गाँव की प्रियंका खड़से बताती हैं कि रोज चिंता रहती थी कि सुबह पानी भरने जाना है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।